

ग्रसाधारण

EXTRAORDINAR

भाग II---खण्ड 3---उपल्लंड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORS

tio 235]

नई विल्लो, बृहस्यतिवार, मई 23, 1974/ज्येष्ठ 2, 1896

No. 235]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 23, 1974/JAISTHA 2, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में रखा जा सर्वे ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 23rd May 1974

S.O. 319(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 305(E), dated the 30th May, 1973 (here-inafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as the Bihar Cooperative Weavers' Spinning Mills Limited, Mokameh (Bihar) or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities

accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period;

And whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended by a further period of one year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order by a further period of one year.

[No, F. 28013/39/73-NTC] D. K. SAXENA, Jt. Secy.

स्रीयोगिक विकास मंत्रालयं

श्रादेश

नई दिल्ली, 23 मई, 1974

का० ग्रा० 319 (ग्र).—-यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के श्रीद्योगिक विकास मंवालय के श्रादेश सं० का० श्रा० 305 (उ०) तारीख़ 30 मई, 1973 (जिसे इसमें इसके परचात् उकत श्रादेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास श्रीर विनियमन) ग्रिधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रोषणा की थी कि उकत श्रादेश (बैंकों ग्रीर वितीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्यों से सम्बन्धित को छोड़ कर) के जारी किए जाने की तारीख़ से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाशों, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्तों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी श्रादेशों या श्रन्य लिखतों का प्रवर्त्तन, जिसका बिहार कोन्नापरेटिव वीवर्स स्थितिंग मिल्स लिमिटेड, मोकामेह (बिहार) नामक श्रौद्योगिक उपक्रम या ऐसे श्रौद्योगिक उपक्रम का स्थामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त ऐसे श्रौद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हो, एक वर्ष की ग्रवधि पर्यन्त निलम्बित रहेगा श्रौर उक्त तारीख़ से पूर्व उक्त श्रधीन प्रोद्भृत या उद्भूत होने वाले सभी श्रिधकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं ग्रौर दायित्व उक्त श्रवधि पर्यन्त निलम्बित रहेगे ;

श्रौर यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त श्रादेश को श्रवधि एक वर्ष के लिए श्रौर बढ़ाई जानी चाहिए ;

अतः, श्रवः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास श्रीर विनियमन) प्रधिनियम, 1951 (1951 का 65) को धारा 18 च ख की उत्थारा (2) द्वारा प्रदत्त णक्तियों का प्रयोग करने हुए, उक्त श्रादेश की श्रवधि एक वर्ष के लिए श्रीर बढ़ाती है।

[सं० फा० 28013/39/73--एन० टी० सी०] विनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव।